†[श्री जलालुद्दीन अंसारी "बेबाक": मैं शुक्रिया अदा करता हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने इस सवाल के जवाब में अपने को समर्पित किया है और सरकार से मांग करता हूं कि जो सीनियर अफसरान हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने पेंशन ले ली है, उन्हें भी कुछ न कुछ सम्मान राशि दी जाए। वे सरकार के शुभचिंतक हैं। उन्हें भी कुछ न कुछ दिया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई करके उन्हें भी सम्मानित करे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।]

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं भी इसके साथ अपने को जोड़ना चाहूंगा। जब निजी क्षेत्र में ऐसे कोई कर्मचारी होते हैं तो ऐसे प्रबंधकों को निश्चित तौर पर सजा मिलती है।

2.00 P.M.

लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा होगा तब तो फिर कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र तो ऐसा होना चाहिए कि वह देश के लिए एक उदाहरण बने। लेकिन वह स्थिति बन नहीं पा रही है। कृपा करके मुझे भी इसके साथ जोड़ना है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA): It is 2.00 p.m. now. Members have to seek clarifications on the statement made by Shri Mulayam Singh Yadav regarding procurement of SU-30 MK aircraft. These names are with me. I will read out the names.

Shri John Fernandes. Not present.

Dr. Y. Radhakrishna Murty.

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[The Vice-Chairman (Shri Triloki Nath Chaturvedi) *in the Chair*]

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

Procurement of SU-30 MK Aircraft

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Sir, on behalf of my party, I support the agreement for the purchase of the SU-30 MK aircraft on three counts. One is the need for augmenting our air-defence system, which is long due. It is said that for the last ten years there was almost a drought in acquisition of defence aircraft. It is also said that our combat aircraft are ageing and probably they may have to retire within ten years. Pakistan is acquiring the most modern aircraft, the so-called P3C Orion maritime reconnaisance plane under the Brown Agreement with Harpoon missiles.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I am sorry. I hate to intervene, but I have to remind the hon. colleague that the hon. Minister has to leave at 2.30 p.m. and we have to finish this. So, it will be better if you will confine yourself to pointed questions for seeking clarifications. This is my only submission to you.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY: The agreement is an indication of the enduring friendship which we are having with Russia even though the Governments have changed qualitatively. The super power has been almost pressurising us directly or indirectly to stall our defence preparedness. This is evident in the case of our Agni missile, in the case of the cryogenic rocket technology transfer to us, in the case of our purchase of Mirage 2000 deal with France etc. In all these cases it is the U.S. pressure that is stalling the help to us from other countries for our defence preparedness.

I want to know from the Defence Minister whether we are going to have deals with similar

intention, withstanding the pressure from the super power, in augmenting our other defence forces also. It is said that our MIG-27s require to be augmented, modernised and updated. This is also another area in which we will have to collaborate with Russia.

Another thing is that we are told that the super surveillance radar system which we are seeking very much for Delhi, Mumbai and other air stations is being delayed because of the pressure from the U.S. Pressure has been put on Reytheons, the agency which is supposed to supply that system to us. I want to know if it is correct. Reytheons has been delaying it for the last two years or more because of the U.S. pressure in this regard.

I also want to know if the civilian aircraft can be built in our country with the help of Russia because it has been reported in some of the newspapers of today that Russia has offered us such a help. Because of the need of self-reliance in our defence as well as in other areas, we need the help of Russia. We need the help of similar other countries to withstand the pressure from the U.S.A.

I want to know from the Defence Minister whether he has got all these things in his mind for improving our defence capability.

Thank you, Sir.

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Sir, I have a very few pointed questions for the hon. Defence Minister.

The country would like to know the price of this plane. I understand its price is between Rs. 150 crores and 185 crores. We would like to have precise information on that.

Secondly, I understand there is an agreement with Russia to manufacture this plane here. What is the time frame for this?

I have got a more basic question to ask. Sir, do we need this kind of a plane? It is known as 'strategic nuclear bomber'. Not even a tactical nuclear bomber, but strategic nuclear bomber. Do we have a nuclear bomb? Do we propose to drop one on anybody? If not, why are we going in for it? If this plane is to be used for carrying 30 tonnes of TNT, then there are fare cheaper ways of doing that. If a huge plane like this is carrying only TNT, then any country can shoot it down as an early target. It will not be shot down only if it is carrying a nuclear bomb. Everything that we expect to do with Sukhoi-30 can be done easily through missiles. The point is why we have put the Agni missile project into deep-freeze, because, a missile like that can carry TNT or anything as fast as we like. 'Agni' is an intermediate range missile. Does it not show that we are doing it under foreign pressure? Sir, you know, we know, and everybody knows, that we are not proceeding with the missile programme only under foreign pressure. Dr. Abul Kalam has made it clear that we are entirely self-sufficient when it comes to manufacture of missiles on our own. So, this type of purchase does not make much sense. Missile defence will be much more effective and much more economical than this kind of conventional warfare. That is what I have to say. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Shri Surinder Kumar Singla. The hon. Member is absent. The hon. Defence Minister has to go at 2.30, but I find many Members are not here to seek clarifications.

Shri Ish Dutt Yadav.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो एस.यू. 30 खरीदने का जो करार हुआ है, उसके लिए मैं ही नहीं बल्कि राष्ट्र के सभी लोग प्रसन्न हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी अत्यंत आवश्यकता थी।

महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता और माननीय रक्षा मंत्री जी से केवल दो प्रश्न करना चाहता हूं। मेरा

पहला प्रश्न यह होगा कि अभी तक रक्षा के जितने सौदे हुए हैं, सब में दलाली की बू आई है और दलाली का प्रकरण न केवल संसद में बल्कि पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय रहा है जिस से देशवासियों के मन में बराबर यह संदेह रहा है कि रक्षा सौदों में दलाली हुई है। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब की बार जो यह एग्रीमेंट हुआ है, उस में इस तरह की कोई बात न आने पाए, इसके लिए आप ने क्या कारगर और ठोस कदम उठाए हैं। इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न होगा कि यह जो एस.यू. 30 लिए जा रहे हैं, इनकी कीमत और गुणवत्ता के बारे में अर्थात् इसके गुण अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ रहा है?

ये मेरे दो प्रश्न थे जिनका माननीय रक्षा मंत्री जी से मैं स्पष्टीकरण चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो विमान खरीदे गए हैं, पहली बात तो उनको बधाई, बहुत-बहुत बधाई, लेकिन जब यह विमान भारत में बनाए जाएंगे तो कितने प्रतिशत पुर्जे हमें आयात करना होंगे? क्या पूरे के पूरे आयात करके उनको यहां केवल असेम्बल करेंगे? दूसरी बात, मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत में जो आधुनिकतम प्रक्षेपास्त्र बनाए जा रहे हैं, क्या उनका प्रयोग इन विमानों के माध्यम से संभव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? तीसरी बात, यह जो हमारे पास विशेष आयुध-सामग्री है उनका प्रयोग करने के लिए क्या उन विमानों में कोई हमें परिवर्तन करना होगा या जिस रूप में विमान खरीद रहे हैं उसी रूप में हम इसका प्रयोग कर सकेंगे? चौथी बात, हम एवियोनिक्य भी बनाने जा रहे हैं रूस के सहयोग से, हमारे देश में विमान निर्माण का जो इतिहास रहा है, विमान निर्माण के विकास का, वह बहुत कोई अच्छा नहीं रहा, हमें बहुत समय लगता है, तो यह कब तक पूरी हो जाएगी परियोजना? कोई स्पष्ट घोषणा आप इस संबंध में कर सकेंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): धन्यवाद। श्री ज़ाहिदी। कृपया आपको बेहतर होगा कि आप अपनी सीट से बोलें तो वह रिकार्ड में आ जाएगा क्योंकि दिक्कत होती है रिपोर्टस को।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): मैं पीछे जाकर बोलूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जहां आपकी अपनी सीट है। मैं यह आपकी सुविधा के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी: ठीक है, शुक्रिया। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं उधर जाऊंगा तो समय चला जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): चलिए, कोई बात नहीं।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से स्पष्ट पूछना चाहूंगा, यह सवाल हलका सा आ भी चुका है, कि जो अब हमारा करार हुआ है और जो हम रसियन प्लेन ले रहे हैं, लड़ाकू प्लेन, उन प्लेन में और दूसरे प्लेन, जो दूसरे बड़े मुल्क कहलाते हैं वह सप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों में लड़ाई के हिसाब से किसको क्षमता ज्यादा है, किसकी स्ट्राइक केपेबिलिटी ज्यादा है? क्या इस स्ट्राइक केपेबिलिटी या लड़ाई की क्षमता में मिसायल इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसा कि मलकानी जी ने सवाल किया था। दूसरा, जो हमारे प्रोक्योरमेंट लेने की जो कीमत प्रोवीजन हैं, उसमें हम इससे सस्ता कोई प्लेन पा सकते थे या नहीं पा सकते थे? तीसरा, तजुर्बे के एतबार से, तजुर्बेगाह से अनुसाधन जहां होता है वहां पर यह रहता है कि यह अच्छा स्ट्राइक प्लेन है या किसी जंग में यह अच्छी क्षमता दिखा चुका है? यह भी एक सवाल इसमें पैदा होता है। शुक्रिया।

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I just want to seek one or two clarifications. It has been mentioned in the statement that the contract permits licenced production of the aircraft in India by HAL for subsequent supplies, I would like to know from the Minister: what he implies, "subsequent supplies". I would also like to know from the Minister whether any undertstanding has been reached not to supply SU-30 MK aircraft to countries inimical to India's interests.

It is also learnt that the first batch of aircraft to be delivered by 1997 would be less advanced than the fourth and final lots of aircraft. If it is so, would the first batch of aircraft be comparable to the fourth and final lots of aircraft. That's all.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

Sir, on the statement laid on the Table of the House, I would like to seek some clarifications. The hon. Minister has indicated that there are two significant features of the contract. One is that the Russian agencies have agreed to permit the DRDO to participate in the R&D and joint development of avionics for the aircraft. In the SU-30 aircraft, are western avionics being used or are Russian avionics being used? That is my question. Secondly, if Russian are up to the mark as far as the technology is concerned? If they are western, then, how do we plan to produce or participate in the R&D and joint development?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): As I have been requesting, please be brief.

SHRI PREM CHAND GUPTA: I am brief. As for the subsequent production by the HAL, do we plan to take up production on a large scale? If it is so, what is the number of such aircraft we will be in a position to produce?

My third question is.....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) : गुप्ता जी, आप दो तक ही अपने आपको सीमित रखिए और कुछ समय मंत्री जी को भी तो दीजिए।

SHRI PREM CHAND GUPTA: With the disintegration of the USSR, our defence armament industry and defence forces are suffering from non-supply of spare parts. Has the hon. Minister taken care of this aspect?

Thank you.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank the hon. Defence Minister and also the hon. Minister of State for Defence for having entered into a crucial agreement with Russia for the purpose of production of 40 SU-30 aircraft in India by both the countries collaborating together. But the statement by the hon. Minister is very brief. It does not give, though we know very well,.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): From 2.30 p.m. onwards, we have the Private Members' business.

SHRI V. NARAYANASAMY: Before 2.30 p.m., we can take 5-10 minutes more. There is no problem. It is a very important subject. It concerns the defence of the country. Therefore, let us not hurry up on this subject.

The hon. Minister should have given a little more information to the House. But, unfortunately, the statement gives only two or three points. Sir, I would like to know whether there is going to be a transfer of technology after some time. When the production starts, when both of them collaborate, will there be any transfer of technology agreed to between both the countries?

Another important aspect is about the special features. What are the special features? Will the hon. Minister be able to give us the special features of this aircraft? We are not technical persons. If he is able to give us that information, let him give that. It is a defence subject. It is for the hon. Minister to decide.

We have the information that computers have to be developed for the purpose of this aircraft; one is to be developed in India and another in Russia. That is the brain behind the entire aircraft which is to be fitted in the aircraft. Is it a fact that both have to be developed, one in Russia and the other in this country? In defence navigation, a very important aspect is the Global Positioning System which will be able to identify the aircraft of enemy countries. I have got the information that it will be able to identify 17 positions out of 20. I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact. I want more information from the hon. Minister, the

information that he can part with in this House, so that we can appreciate better the agreement entered into between the Government of India and the Russian Government for the purpose of having acquisition of more aircraft, sophisticated aircraft, in our country. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): रक्षा मंत्री महोदय, आप जवाब शुरू कीजिए।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने देश की जनता को रक्षा के संबंध में जानकारी दिलाने के लिए मुझे अवसर दिया। सभी माननीय सदस्यों ने इस रक्षा सौदे का स्वागत किया है, इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

माननीय कृष्णमूर्ति जी ने तो चिंता व्यक्त की है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अमरीका का कोई दबाव भारत पर नहीं है और अमरीका तो छोड़िए, हिंदुस्तान का रक्षा संबंधी जो भी कार्यक्रम है, वह दुनिया के किसी देश के दबाव के कारण नहीं है। भारत आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ेगा। जहां तक कीमत का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो बातचीत कर रहा है फ्रांस के साथ मिराज 2000 के बारे में, उसकी कीमत हमारे इन एस.यू. 30 एम. के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। यह अखबारों में भी छपा है। जहां तक इन जहाजों की क्षमता का सवाल है, अभी तक विश्व में इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनकी पहली खेप मार्च तक आ जाएगी और सन 2001 तक ऐसे 40 विमान हमारे पास हो जाएंगे। बाद में अगर आवश्यकता होगी तो हम रूस के सहयोग से अपने यहां इन विमानों को बना सकेंगे। हम अपने इन्फास्ट्रक्चर से अपने यहां इन्हें बनाएंगे। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हम समझौते के अंतर्गत रूस बाध्य होगा अपनी टेक्नोलोजी को हिंदुस्तान को देने के लिए।

जहां तक दलाली का सवाल है, समय-समय पर हम कहते आए हैं कि रक्षा सौदों में दलाली का कोई सवाल नहीं है। हिंदुस्तान अपने रक्षा सौदों के मामले में कुछ काम नहीं कर पा रहा था। इसकी एक वजह थी और वह वजह सभी माननीस सदस्यों को मालूम है। सबको भय लगता था, डर लगता था कि अगर हम इस तरह का कोई सौदा करेंगे तो कहीं न कहीं हम पर धब्बा लगेगा, दाग लगेगा। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ एजेंसियों के माध्यम से आपका राजनीतिक जीवन कभी भी खत्म किया जा सकता है। तब आपका त्याग, तपस्या, सब धरा रह जाएगा। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

महोदय, इस दृष्टि से सरकार ने यह एक साहसिक कदम उठाया है। इसमें एक तरफ तो यह ध्यान रखा गया है कि बिचौलिया कहीं नहीं आएगा और इस संबंध में रूस के उच्चतम अधिकारियों से लिखवाकर ले लिया गया है कि इसमें कोई भी दलाल या बिचौलिया नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो करार किया गया है, उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर कभी यह जानकारी मिली कि सौदे में कोई दलाली ली गई है तो सौदा रद्द कर दिया जाएगा और उस कंपनी से पूरा का पूरा पैसा वापस ले लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जहां तक मार की क्षमता की जरूरत क्यों पड़ गई, यह मैं अलग से आपको बताऊंगा। यह ऐसा लड़ाकू विमान है जो दोनों काम करेगा। यह हमला भी करेगा और जो आने की कोशिश करेगा उसको रोकेगा भी और उस पर मार भी करेगा। मुझे खुशी होगी अगर तीन तारीख को बंगलौर में इसका जो शो हुआ था उसमें आप शामिल होते। आप स्वयं देख लेते कि जो इसमें दिखाया गया कि यह कितना शक्तिशाली लड़ाकू विमान लिया गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मंत्री जी, आपका निमंत्रण तो मुझे भी प्राप्त हुआ था लेकिन वहां पहुंचना मुश्किल था।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर आप किसी कारण वश नहीं आ पाए तो आपको हम अवश्य पहुंचा देते। अब अगर आगे होगा तो हम पहुंचा देंगे। हम दोबारा देखने जाएंगे तो आपको साथ ले लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव: जहां तक कीमत का सवाल है, इन 40 विमानों की कीमत 6030 करोड़ रूपया है। अभी 40 जहाज ही आएंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रूस की टैक्नोलोजी लेकर जितनी जरूरत है वह हम बनाएंगे। यह भी सवाल पूछा गया है कि इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जहां तक रैंक का सवाल है, मैं बतला चुका हूं कि इसकी तुलना है ही नहीं। इसका इंजन भी बेहतर है। युद्ध की दृष्टि से बचाने का और हमला करने का काम करेगा। इसमें कोई क्वालिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उसी क्वालिटी का और अपनी टैक्नोलोजी लेकर उसी तरह का होगा। तो यह बहुत सोच समझकर और गंभीरता से विचार-विमर्श करके इस काम को किया गया है।

जहां तक यह सवाल पूछा गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी। मिसाइल का कार्यक्रम बंद नहीं किया जाएगा और वह चालू रहेगा।

जहां तक मिसाइल का एक बार प्रयोग हो जाता है उसके बाद अभी दोबारा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, जो एस.यू.-30 का विमान है, वह हमने आपको बतला दिया है। जहां तक रूस और पाकिस्तान का सवाल है, इसके लिए तो हम रूस का स्वागत करेंगे कि रूस ने अभी तक रक्षा संबंधी कोई भी पुर्जा पाकिस्तान को नहीं दिया है। अभी हमारी दो मुलाकातें हुई। प्रधान मंत्री और उसके बाद रक्षा मंत्री से मैंने स्पष्ट अनुरोध किया कि कोई किसी प्रकार की रक्षा सामग्री आप पाकिस्तान को न दें और आप मेरे मित्र हैं और इस तरह गहरे मित्र बन गए हैं कि इसका पालन आप करें। उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हम पाकिस्तान को कोई भी रक्षा संबंधी सामग्री या पुर्जा कुछ भी नहीं देंगे। एक जगह वह दे भी रहे हैं। पाकिस्तान में वह सामान जा रहा है। उसके लिए भी हमने अनुरोध किया है। उन्होंने हमसे वायदा किया है कि अगर एक मुल्क हमसे पुर्जा लेकर के हथियार बनाकर के पाकिस्तान को सप्लाई करेगा, तो हम इस पर विचार करेंगे कि उसे हम पुर्जा दें या न दें। इस तरह से रूस हमारा साथ दे रहा है। हम इस सदन के माननीय सदस्यों से कहेंगे कि हमारा जो मित्र रूस है उसका यहां पर स्वागत करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए वह कितना सहयोग कर रहा है। जहां तक सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यो पड़ गई थी, हम शांति चाहते हैं और शांति के पक्षधर है। गांधी जी ने शांति का उपदेश दिया और नेहरू जी ने भी। लेकिन फिर भी हम धोखा खा गए, वह अलग चीज है। लेकिन हम शांति पर चलेंगे और अगर कहीं किसी प्रकार से जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान अपने हथियारों से बाज नहीं आ रहा है।

आपने देखा कि मुख्य मंत्री फारूख अब्दुल्ला पर किस तरह से जानलेवा हमला किया गया था, किस तरह से उनकी जान लेने का षड्यंत्र किया गया था और तब जब शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के जन्मदिवस पर वे श्रद्धा-सुमन पेश करने जा रहे थे। उससे पहले आपने देखा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सात नेता मार दिए गए और 38 घायल हो गए। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम शांति चाहते हैं लेकिन अगर वह हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उसको जवाब देने के लिए शक्तिशाली सेना बनाने के लिए जो भी उपाय हमें करने पड़ेंगे, वह हम करेंगे।

दूसरी बात यह है कि हम हथियारों की दौड़ में नहीं पड़ना चाहते हैं। माननीय नरेन्द्र मोहन जी नए सदस्य हैं, हम भी नए हैं। उनको यह पता है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने उनके यहां चाय पी थी, मैंने भी एक बार यहां चाय पी थी इनके साथ, इनको याद है तो हम कभी भी हथियारों की दौड़ में नहीं चलते हैं। समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य है कि हथियारों की दौड़ में नहीं पड़ेंगे और न पड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हथियार लाने की कोशिश करेगा, इस तरह से लगातार हरकतें जारी रखेगा तो हमें अपनी सेना को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि वह ईट का जवाब पत्थर से दे सके। इसकी आज बहुत आवश्यकता है।

तीसरी बात यह है कि इस स्तर पर हम अपने माननीय सदस्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करना चाहते हैं, प्रार्थना भी करना चाहते हैं और सुलह भी करना चाहते हैं कि पहले एक संकल्प लिया गया था देश के रक्षा संबंधी मामलों में कि पूरा देश एक रहेगा और वह संकल्प जब लिया गया था उस वक्त हम विद्यार्थी थे लेकिन उस संकल्प को कायम रखने के लिए इस मुद्दे पर हम सबको एक होना चाहिए। जहां तक राजनीतिक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक विचारधारा का सवाल है, हमारे और आपके तमाम मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों के मैदान हैं जहां हम बहस कर सकते हैं लेकिन रक्षा संबंधी मामलों में हम चाहते हैं कि सब उस संकल्प को ज्यों का त्यों रखें। पहले जैसे एक हुए थे उसी तरह से एक रहें और इस संकल्प को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। यह हमारी अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने इस वक्तव्य से सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। यदि माननीय सदस्य कुछ और पूछना चाहते हैं तो उसका जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं।

SHRI K.R. MALKANI: My question has not been answered.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): We have to take up the Private Members' Business.

SHRI K.R. MALKANI: I know. I will take only half a minutes. It is such an important point. This is a strategic nuclear bomber, not a tactical nuclear bomber. Do you have a bomb? Do you propose to drop it anywhere? In any case, missiles can also carry nuclear load. Nobody said that this is not a good plane. This is a very good plane. Will not a missile programme be more effective and less expensive than Sukhoi-30? That question is not answered.

श्री मुलायम सिंह यादव: ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और जानते भी हैं और जानते हुए भी कि कुछ रक्षा संबंधी मामले ऐसे भी होते हैं जिनको सदन में या जनता के बीच में बताया नहीं जा सकता है लेकिन इतना हम कहना चाहते हैं कि किसी भी मौके पर कितना भी बड़ा मुकाबला होगा, हिंदुस्तान उसका जवाब देने के लिए तैयार है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मंत्री जी, आपको धन्यवाद। जहां तक मैं समझता हूं कि सुरक्षा का प्रश्न है, जिस संकल्प का आपने ज़िक्र किया, उसमें पूरा देश एकमत है और दोनों सदन तो हैं ही। मैं समझता हूं कि उसमें किसी संदेह की गुंजाईश होनी ही नहीं चाहिए। Now, the Finance Minister will lay on the Table of the House the Supplementary Demands for Grants (General) 1996-97.

SUPPLEMENTARY-DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1996-97 (DECEMBER, 1996)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General), 1996-97 (December, 1996).

PRIVATE MEMBERS' LEGISLATIVE BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Now Bills to be introduced. Shri Gurudas Das Gupta, not present. Shri Suresh Pachouri.

The Rural Electrification Bill, 1996

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Rural Electrification Authority to ensure uninterrupted electricity supply to farmers for their agricultural activities and for providing at least Ek Batti connection to every house and hut in rural India and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

The High Court of Madhya Pradesh (Establishment of a Permanent Bench at Bhopal Bill, 1996.

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Madhya Pradesh at Bhopal.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

The Abolition of Begging Bill, 1996.

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the abolition of begging which has become a menace at the places of tourist importance, religious places, railway and bus stations and market places and other places used by general public and has become nuisance for the tourists and the general public due to penetration of anti-social elements in this field and matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Miss Saroj Khaparde, not there. Shri V. N. Gadgil.

The Disclosure of Assets by Ministers, Members of Parliament and Public Servants Bill, 1996

SHRI V. N. GADGIL (Maharashtra): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for disclosure of assets by Ministers, Members of Parliament and Public Servants.

The question was put and the motion was adopted.